हवाई जहाज से यात्रा करना सुविधाजनक नहीं होगा । इन्दौर प्रदेश का सब से बड़ा औद्योगिक, व्यावसायिक और व्यापारिक केन्द्र है, जिसके आसपास देवास, उज्जैन, नागदा तथा रतलाम प्रमुख औद्योगिक नगर हैं । इन्दौर को नई वायु सेवाओं की आवश्यकता है ।

अतएव मेरा नागरिक विमानन मंत्रालय से आग्रह है कि अगले माह से प्रारम्भ की जा रही नई बोइंग एवं एअर विमान सेवाओं में इन्दौर को सम्मिलित किया जाए तथा इन्दौर और बम्बई के बीच बदले जा रहे टाइमिंग्ज को न बदलते हुए यथावत् रखा जाए

(vi) NEED FOR FINANCIAL ASSISTANCE TO WEST BENGAL GOVERNMENT TO PROVIDE RELIEF TO NON-ASSAMESE EVACUEES FROM ASSAM

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Sir, the Government of West Bengal requested several times regarding the release of funds to the West Bengal Government towards reimbursement of expenditure incurred for affording temporary relief and shelter to the non-Assamese people, who have been forcibly evicted from Assam, and are now living in camps in West Bengal.

Sir, the State Government repeatedly urged upon the Central Government to provide funds to continue necessary measures for providing relief and shelter to these persons. So far, neither has any reply been sent, nor any fund released, by the Central Government.

Under these circumstances, I urge upon the Government to provide necessary financial assistance to the West Bengal Government immediately to meet the expenditure already incurred, and to be incurred, for the relief of evacuees till they can return to their homes in Asam. I also demand that the Minister should make a statement in the House in this regard.

(vii) NEED TO PUBLISH AN ANTHENTIC HINDI VERSION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, संविधान के अनुसार हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है और कुछ समय के लिए अंग्रेजी कामचलाऊ भाषा । परन्तु खेद की बात है कि हिन्दी को आज भी अंग्रेजी की सहचरी बना कर रखे जाने की चेष्टा की जा रही है ।

भारत का संविधान मूल रूप से हिन्दी में बनाना चाहिए था, लेकिन खेद की बात है कि आज तक उसका हिन्दी में ऐसा प्रमाणिक अनुवाद भी प्रकाशित नहीं किया गया, जिसे न्यायालयों और विधि जगत में मान्यता प्राप्त हो । हिन्दी के साथ इससे बड़ा और कोई अन्याय नहीं हो सकता । यह आजाद भारत एवं देश के नागरिकों के सिर पर कलंक है ।

इसी प्रकार सरकार को अन्य भारतीय भाषाओं में भी संविधान की प्रमाणिक प्रतिलिपि तयार करानी चाहिए ।

देश के प्रत्येक नागरिक के पास संविधान के प्रति गीता, रामायण, बाइबल और कुरान की तरह रहनी चाहिए । अतः इसका सस्ता संस्करण प्रकाशित कराए जाने की नितान्त आवश्यकता है ।

DEMANDS FOR GRANTS, 1981-82—*contd.*

Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Reconstruction—*contd.*

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Tapeshwar Singh may speak.

श्री तपेश्वर सिंह (विक्रमगंज) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की जो डिमांड यहां विचारार्थ प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय : आप जरा एक मिनट बैठें ।